हम, हस्ताक्षरकर्ता, अपने निम्न 11 साथी नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित है:

1 श्री वरावर राव
2. श्रीमती सुधा भारद्वाज
3. श्रीमती शोमा सेन
4. श्री आनंद तेलतुम्बडे
5. श्री गौतम नवलखा
6. श्री अरुण फ़रेरा
7. श्री वर्णन गोंसाल्विस
8. श्री सुरेंद्र गाड्लिंग
9. श्री महेश राउत
10. श्री सुधीर धावले
11. श्री रोना विल्सन

ये 11 मानव अधिकारों के पुरोधा और कार्यकर्ता दशकों से भारत के सबसे ग़रीब और हाशिए पर धकेल दी गई जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, इनमें से कई बेहतरीन विचारक, लेखक और कवि हैं। फिर भी आज इन्हें राजनीतिक कैदी बनाकर जेलों में बंद किया गया है। महाराष्ट्र की जिन जेलों में ये सब कैद हैं उनमें कुछ कैदियों की कोविड-19 से मौत हो चुकी है और कई इससे संक्रमित हैं, इसके बावजूद इन्हें ज़मानत नहीं दी जा रही।

असम में राज्य द्वारा मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ बाद-बार आवाज़ उठाने वाले अखिल गोगोई को भी ज़मानत नहीं दी जा रही है।

ये कार्यकर्ता अपराधी साबित नहीं हुए हैं। न ही ये देश छोड़ कर जाने और क़ानून से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम माँग करते हैं कि इंसानियत के नाते इन्हें तुरंत ज़मानत दी जाए क्योंकि देश में तेज़ी से फैल रही महामारी इनके लिए खतरा बनी हुई है। हमें यह भी पता चला है कि 80 वर्षीय श्री वरावर राव की तबियत पहले ही बिगड़ चुकी है और उन्हें एक पुलिस अस्पताल में भेजा गया है।

यह भी विचलित करने वाली बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा ज़रगर, जो गर्भवती भी हैं, को भी CAA के खिलाफ विरोध करने के लिए गिरफ्तार किया गया है और उनकी ज़मानत अर्ज़ी ठुकरा दी गयी है। जिसकी वजह से उनकी और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे दोनों की ज़िंदगी पर ख़तरा मंडरा रहा है। दिल्ली में CAA, NPR और NRC को चुनौती देने वाले शांतिपूर्ण आंदोलनों की अगुवाई करने के लिए जामिया और जेएनयू के अन्य युवा छात्र कार्यकर्ताओं को भी कोविड-19 लॉकडाउन के दौर में आपराधिक मामलों में फँसाकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है।

उपरोक्त 11 कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सफूरा और इन तमाम छात्रों को भी ज़मानत दी जानी चाहिए।

यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी जेलों में बढ़ते कोविड-19 के संक्रमण के ख़तरे की बात कही है। उल्लेखनीय है कि अमरीकी बार एसोसिएशन - सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने भारत सरकार से गुज़ारिश की है कि तुरंत भारतीय जेलों में बंद मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए।

हम इससे बहुत चिंतित हैं कि मौजूदा हालात हैं जाने-माने मानव अधिकार कार्यकर्ताओं और असहमति ज़ाहिर करने वाले छात्रों को जेल में बंद किया गया है। इस वक़्त सारा ध्यान महामारी को रोकने, जेलों और उनके बाहर, में लगाया जाना चाहिए न कि देश में असहमति की आवाज़ों को कुचलने में।

एक बेहतर भारत के लिए निस्स्वार्थ भाव से काम कर रहे हमारे देश के जाने-माने सामाजिक कार्यकर्ताओं में से कुछ को और असमति दर्ज करवाने वाले छात्रों को अगर जानबूझकर जेलों में बंद किया जा रहा है जहाँ कोविड-19 जैसी महामारी का ख़तरा उनका इन्तेज़ार कर रहा है, तो इन लोगों पर इस महामारी के दुष्प्रभाव की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार पर ही डाली जानी चाहिए।

हम भारत के लोग, साथ ही पूरी दुनिया भी, ये ध्यान से देख रहे हैं कि हाशिए पर धकेली गयी जनता और लोकतांत्रिक असहमति के पक्ष में खड़े लोगों के साथ ये सरकार क्या सलूक करती है। सभी कार्यकर्ताओं और मानव अधिकारों की रक्षा करने वालों को तुरंत ज़मानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हमारी यही माँग है।